RNI NO. : MAHHIN/2019/77511 मुंबई : शुक्रवार 15 दिसंबर 2023 वर्ष 05 अंक 233 संपादक : फैसल शेख पृष्ठ : 4 कीमत : 03 रुपये

दैनिक
रोकठोक लेखनी
खबरें बे-रोकटोक

Read E Newspaper at Paper Boy App, Magzter App, Jio News App, Paytm App, Dailyhunt App

महाराष्ट्र विधानसभा में महादेव बेटिंग एप की गूंज...

गृहमंत्री फडणवीस बोले- SIT और ED कर रही जांच

महाराष्ट्र : महाराष्ट्र विधानसभा के शीतकालीन सत्र में गुरुवार को महादेव बेटिंग एप घोटाले की गूंज सुनाई पड़ी. विधानसभा में बताया गया कि महादेव एप घोटाले का पैसा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया गया है. राज्य के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बिल्डर की पहचान हो गई है. मामले की एसआईटी और ईडी जांच कर रही है.

सदन की कार्यवाही के दौरान विपक्षी विधायकों की ओर से कई सवाल भी किए गए. देवेंद्र फडणवीस ने सदन में सवालों का जवाब देते हुए देश के फिल्मी सितारों से भी बड़ी अपील की. उन्होंने कहा कि फिल्मी सितारों से कहा कि भविष्य में वो ऐसे किसी गेमिंग एप का प्रमोशन न करें. उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियां अगले दो महीने में जांच पूरी कर देंगी. मामले की एनआईए जांच जरूरी नहीं है, ईडी पहले से ही जांच कर रही है. विधानसभा की कार्यवाही के दौरान बीजेपी नेता आशीष शेलार ने कहा कि महादेव एप के जरिए कमाया गया पैसा बिल्डरों के जरिए निवेश किया जा रहा है. इसके साथ-साथ उन्होंने इंफ्रा प्रोजेक्ट में भी पैसा लगाने का आरोप लगाया. जवाब में गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि मामले की ईडी जांच कर रही है. मुंबई पुलिस के जरिए भी जांच हो रही है.

सदन की कार्यवाही के दौरान महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता विधायक नाना पटोले ने पूछा कि इस पूरे मामले में राज्य का आईटी सेल क्या कर रहा था? फडणवीस ने जवाब में बताया कि फिजिकली जो जुआ बंद है उसे इन लोगों ने ऑनलाइन शुरू किया था.

महादेव एप पैरेंट कंपनी, इसके 67 एप

राज्य के गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महादेव एप एक पैरेंट कंपनी है जो सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल के जरिए चलाई जा रही है. इसके कुल 67 एप हैं और सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. इनका पोर्टल भी है जिसमें महादेव एप की 80-20 फीसदी पार्टनरशिप है. इसका रजिस्ट्रेशन साउथ अमेरिका के वेनेजुएला में किया गया है.

जालना में गर्भवती महिला की हत्या मामले में 6 को उम्रकैद

जांच में हुआ ये खुलासा...

महाराष्ट्र : महाराष्ट्र के जालना में जिला एवं सत्र कोर्ट ने संपत्ति के विवाद में 2020 में एक 35 वर्षीया गर्भवती महिला की हत्या के लिए चार महिलाओं समेत छह को उम्रकैद की सजा सुनाई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीएम मोहिते ने बुधवार को यह फैसला सुनाया। अदालत ने हर दोषी पर एक-एक हजार रुपये जुमार्ना भी किया है। जालना के काजीपुरा क्षेत्र में हत्या के समय पीड़िता हिना खान छह माह की गर्भवती थी।

कोर्ट ने दोषी करार दी गई 23 वर्षीया निलोफर जफर खान, 55 वर्षीया नसीमा जफर खान, 60 वर्षीया हलीमा बी, 30 वर्षीया शबाना शाह, 20 वर्षीय अरबाज खान जफर खान और 38 वर्षीय इस्माइल अहमद शाह को सजा सुनाई।

संपत्ति को लेकर पहले से विवाद था

सरकारी वकील भारत खांडेकर के अनुसार, दोषी हिना खान के पहले पति के रिश्तेदार हैं। हिना के साथ उनका कुछ संपत्ति को लेकर विवाद था। नौ अगस्त, 2020 को आरोपी हिना खान के दूसरे पति सैयद मजीद तंबोली के घर में जबरन घुस गए। उन्होंने हिना पर रॉड से हमला कर दिया जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। तंबोली भी घायल हो गया। सदर बाजार थाने में मामला पंजीकृत कराया गया था।

मुंबई में अवैध रूप से रह रहे 9 बांग्लादेशी गिरफ्तार

फर्जी आधार कार्ड बरामद, बैंक अकाउंट भी खुलवाए थे

मुंबई : मुंबई पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर और उसके आसपास के इलाकों में अवैध रूप से रह रहे 9 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कई आरोपियों के पास से फर्जी आधार कार्ड भी बरामद किया है। अधिकारियों ने बताया कि मुंबई क्राइम ब्रांच ने देश में अवैध रूप से रह रहे नौ बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है।

गिरफ्तार किए गए लोग फर्जी आधार कार्ड बनाकर छिपकर रह रहे थे। आरोपी अवैध रूप से भारत से बांग्लादेश में पैसे भी ट्रांसफर करते थे। क्राइम ब्रांच के डिप्टी कमिश्नर (डीसीपी) राजतिलक रौशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'कुल नौ बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है.. वे अवैध रूप से भारत से बांग्लादेश में पैसे भेजते थे। इसमें और भी लोगों ी संभावना हैं... यह एक प्रकार का हवाला लेनदेन करते थे। इसकी अभी जांच चल रही है। आरोपी उन व्यक्तियों के माध्यम से पैसे भेजते थे जो भारत से बांग्लादेश या बांग्लादेश से भारत सीमा पार कर आते-जाते थे।'

गोरेगांव में रिक्शे में मिला क्षत-विक्षत शव, मुंबई पुलिस ने ADR के तहत केस दर्ज किया

मुंबई : मुंबई के गोरेगांव इलाके के संतोष नगर इलाके में एक रिक्शे से एक शख्स का क्षत-विक्षत शव बरामद हुआ. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. डिंडोशी पुलिस द्वारा एडीआर (एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट) के तहत मामला दर्ज किया गया और आगे की जांच की गई. शव की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है. मुंबई पुलिस ने इसकी जानकारी दी है.

फिर शुरू होगा मराठा आरक्षण का आंदोलन?

जरांगे ने सरकार पर बयान बदलने का आरोप लगाया

महाराष्ट्र : महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर से गरमा सकता है। मराठा आरक्षण आंदोलन का नेतृत्व कर रहे मनोज जरांगे पाटिल ने राज्य सरकार पर अपने बयान बदलने का आरोप लगाया है। जरांगे ने कहा कि सरकार ने मराठा आरक्षण के मुद्दे पर अपने बयान बदल दिए हैं। इसलिए वह मराठा समुदाय के अन्य सदस्यों के साथ 17 दिसंबर को एक बैठक करेंगे ताकि यह तय किया जा सके कि अपने आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाया जाए।

इस दिन तक की समयसीमा

मनोज जरांगे ने मराठा समाज को आरक्षण देने के लिए सरकार को 24 दिसंबर तक की समयसीमा दी है। बता दें कि जरांगे अभी अस्पताल में भर्ती हैं। उन्होंने कहा कि 17 दिसंबर को जालना जिले के अंतरवाली सराटी गांव में एक बैठक होगी। बैठक में इस बात पर निर्णय लिया जाएगा कि मराठा आरक्षण आंदोलन को आगे कैसे ले जाना है। जरांगे ने कहा कि वह पहले 24 दिसंबर को बैठक करने वाले थे लेकिन कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिस कारण बैठक को पहले ही बुलाना पड़ रहा है। इस दौरान जरांगे ने छगन भुजबल पर भी निशाना साधा है।

क्या है जरांगे का आरोप?

मनोज जरांगे ने कहा कि सरकार ने पहले ही कहा था कि वह अंतरवाली सराटी में हुई घटना से संबंधित मामले वापस ले लेगी। मगर उन्होंने वहां लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जरांगे ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल की बात सुनने के बाद सरकार ने मराठा आरक्षण पर अपना बयान बदल दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने हमें मराठा आरक्षण के बारे में भी लिखित में नहीं दिया है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, छगन भुजबल ने आरोप लगाया था कि मराठा आरक्षण के लिए जारी आंदोलन के बीच उन्हें पिछले दो महीनों से अपशब्द कहे जा रहे हैं और धमकियां मिल रही हैं। भुजबल ने ये भी कहा था कि पुलिस को जानकारी मिली है कि उनकी गोली मारकर हत्या की जा सकती है।

बीते 1 सितंबर को जालना के अंतरवाली सराटी गांव में मराठा आरक्षण के लिए आयोजित प्रदर्शन हिंसक हो गया था जिसमें पुलिसकर्मियों सहित कुछ लोग घायल हो गए थे।

संपादकीय / लेख

संसद की सुरक्षा में सेंध

वर्ष 2001 में पुरानी संसद पर पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी समूहों के हमले की 22वीं बरसी पर गत 13 दिसंबर को संसद की नई इमारत में सुरक्षा में सेंध की घटना कई सवाल खड़े करती है। ये सवाल इसलिए हैं कि माना जा रहा था कि नई इमारत 96 वर्ष पहले बनी पुरानी संसद की इमारत की तुलना में कहीं अधिक सुरक्षा प्रणालियों और प्रक्रियाओं से लैस होगी। कहा गया था कि नए संसद परिसर में 2001 जैसे हमले करना संभव नहीं होगा। परंतु 2001 के हमलों से तुलना दिल्ली पुलिस, अर्द्धसैनिक बलों और संसद सुरक्षा सेवा तीनों के लिए बेहतर नहीं है। ये तीनों सेवाएं संसद की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं।

वर्ष 2001 में संसद पर हमला लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद ने योजना बनाकर किया था। उस हमले में आधुनिक हथियार शामिल थे। इसके बावजूद वे जिस कार में सवार होकर आए थे वह मुख्य भवन के आसपास भी नहीं पहुंच पाई थी और संसद के भीतर मौजूद करीब 100 सांसदों में से किसी के साथ हमलावरों की शारीरिक झड़प नहीं हुई थी। परंतु बुधवार को हुए हमले में शारीरिक संपर्क भी हुआ। वर्ष 2001 में हमलावरों की कार में गृह मंत्रालय का एक फर्जी स्टीकर लगा हुआ था और सुरक्षा बलों द्वारा गड़बड़ी की आशंका में सतर्क होने के बाद वह कार वापस घुमा ली गई थी। उसके बाद आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी और फिर गोलीबारी में सुरक्षा बलों के आठ कर्मियों और एक माली की मौत हो गई। यह सही है कि 2023 में हुए हमलों के दोषी सामान्य निहत्थे भारतीय नागरिक हैं और इसलिए उन पर संदेह नहीं किया जा सकता लेकिन यह भी खुशकिस्मती ही है कि इस ऑपरेशन की परिकल्पना, योजना और इसके लिए जरूरी संसाधन आदि निहायत हास्यास्पद और शौकिया अंदाज में किए गए, इसलिए इसमें कोई हताहत नहीं हुआ।

दर्शक दीर्घा में दो हमलावर अपने जूतों में छिपाकर जो दो रंगीन धुएं वाले कैन ले गए थे वे किसी जहरीली गैस से भरे नहीं थे और ज्यादातर खेल के मैदानों में इस्तेमाल होते हुए देखे जाते हैं। परंतु यह प्रश्न जरूर पूछा जाना चाहिए कि आखिर दो अन्य षडयंत्रकर्ता इमारत के बाहरी हिस्से के अत्यधिक करीब कैसे पहुंचे जहां उन्होंने नारे लगाए और रंगीन धुएं के कैन इस्तेमाल किए। आंतरिक डिजाइन को लेकर भी पूछताछ होनी चाहिए जहां आगंतुकों की गैलरी सांसदों के निकट बनाई गई है और जहां से एक स्वस्थ व्यक्ति नीचे कूद सकता है। संसद परिसर के भीतर हंगामे से परे इस घटना के बाद सुरक्षा प्रक्रिया पर भी पुनर्विचार किया जाना चाहिए। सांसद जिस लापरवाही से आगंतुकों के पास जारी करते हैं उस पर भी गौर किया जाना चाहिए। दर्शक दीर्घा में जाने वाले लोगों की सुरक्षा जांच का स्तर वैसा भी नहीं था जैसा कि दुनिया और भारत के भी कुछ प्रमुख हवाई अड्डों में देखने को मिलता है। अधिकांश बड़े हवाई अड्डों पर जूतों की अलग से जांच की जाती है। इन दिक्कतों को उन्नत तकनीक से दूर किया जा सकता है लेकिन असल मुद्दा है संसद के आसपास व्यापक सुरक्षा योजना। इसके लिए केवल यातायात तथा पैदल चलने वालों को रोकने या नागरिकों पर निगरानी बढ़ाने के अलावा कुछ कदम उठाने होंगे। अमेरिका में कैपिटल बिल्डिंग पर 6 जनवरी, 2021 को हुए हमले ने भी दिखाया कि सार्वजनिक प्रशासन से जुड़े संस्थान किस तरह अप्रत्याशित हमलों की जद में हैं। भारत जैसे जटिल लोकतांत्रिक देश में कई बाहरी और आंतरिक खतरे हमेशा रहते हैं। संसद की सुरक्षा के जिम्मेदार लोगों को ऐसे खतरों का अनुमान लगाकर पूरी योजना के साथ उनसे निपटने की तैयारी करनी चाहिए। इस प्रक्रिया में जवाबदेही तय करने और सुरक्षा ढांचा मजबूत करने के साथ खुफिया मोर्चे पर भी अधिक मेहनत करने की जरूरत है।

फैसल शेख
(प्रधान संपादक)
+91 99877 75650
editor@rokthoklekhaninews.com
Faisal Shaikh @faisalshaikh_91

'मेरी हत्या हो सकती है', भुजबल ने किया दावा

कांग्रेस बोली- यह OBC-मराठाओं को लड़ाना चाहते हैं

महाराष्ट्र : महाराष्ट्र के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल ने दावा किया है कि उनकी हत्या की जा सकती है। पुलिस की खुफिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए छगन भुजबल ने बुधवार को राज्य विधानसभा में दावा किया कि 'उन्हें गोली मारी जा सकती है और पिछले दो महीने से उन्हें धमकियां मिल रही हैं।' गौरतलब है कि बीते दिनों छगन भुजबल की गाड़ी तक लोग पहुंच गए थे और आरोपियों ने छगन भुजबल को मराठा आरक्षण के खिलाफ ना बोलने को कहा था।

छगन भुजबल ने किया ये दावा

विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान अपने संबोधन में छगन भुजबल ने कहा कि उनकी छवि मराठा आरक्षण विरोधी की बनाई जा रही है जबकि वह मराठा आरक्षण के विरोधी नहीं हैं। बता दें कि छगन भुजबल मराठा आरक्षण को ओबीसी कोटे में शामिल करने का विरोध कर रहे हैं। भुजबल ने कहा कि सभी पार्टियों की तरह वह भी यही रुख अपना रहे हैं कि मराठा समुदाय को ओबीसी कोटे में आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। उन्हें रोजाना फोन पर गालियां और धमकियां मिल रही हैं। बता दें कि मराठा आरक्षण की मांग करने वाले मनोज जारांगे ने भुजबल पर मराठों और ओबीसी वर्ग के बीच तनाव फैलाने का आरोप लगाया था। जारांगे ने कहा था कि भुजबल राज्य का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं।

छगन भुजबल के बयान पर राजनीति गरमाई

छगन भुजबल के विधानसभा में किए गए दावे पर राजनीति गरमा गई है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने आरोप लगाया कि इस सरकार में कोई समन्वय नहीं है। ये ओबीसी के लिए कोई नीति नहीं बनाई है और सिर्फ उनका शोषण कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार आरक्षण से छुटकारा पाना चाहती है और इसके लिए यह ओबीसी और मराठाओं के बीच टकराव पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ताकि इस लड़ाई में वो आरक्षण को भूल जाएं। आरक्षण से बचने के लिए भाजपा ने यह योजना बनाई है। एनसीपी-शरद पवार गुट के नेता रोहित पवार ने इस पर कहा कि छगन भुजबल जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, वह इससे सहमत नहीं हूं। मैं ऐसे भाषणों के खिलाफ हूं। अगर उनकी जान को खतरा है तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और उनकी सुरक्षा बढाई जानी चाहिए। महाराष्ट्र में किसी को जान से मारने की धमकी देना यह ठीक नहीं हो रहा और हम इसके पूरी तरह से खिलाफ हैं।

राजनाथ सिंह ने विपक्ष के हंगामे पर उठाया सवाल, संसदीय मंत्री ने गिनाईं पुरानी घटनाएं

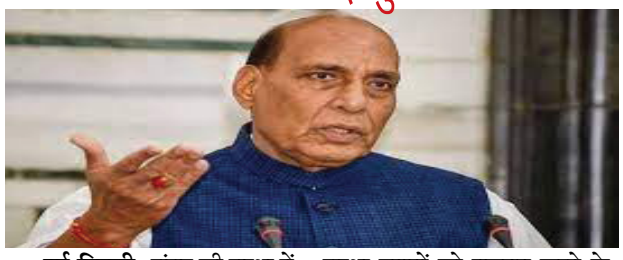

नई दिल्ली: संसद की सुरक्षा में चूक के उच्च स्तरीय जांच के आदेश और सुरक्षा को दुरुस्त करने के लिए जरूरी उपाय किये जाने के बाद भी विपक्ष के हंगामे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए सभी सांसदों ने एक स्वर में निंदा की है। सत्तापक्ष और विपक्ष सभी सांसदों को दर्शक दीर्घा के लिए पास जारी करने में ज्यादा सावधानी बरतने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि कागज फेंकने से लेकर इस तरह की घटनाएं पुराने संसद भवन में पहले भी चुकी हैं। वहीं, संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी ने आपराधिक कानूनों में संशोधनों से जुड़े तीन विधेयकों की अहमियत बताते हुए विपक्षी सांसदों से चर्चा में हिस्सा में लेने की अपील की। जोशी ने साफ किया कि आजादी के बाद से ही दर्शक दीर्घा से कागज फेंकने, नारेबाजी करने समेत सदन के भीतर कूदने की घटनाएं हो चुकी हैं। इन घटनाओं के बाद तत्कालीन लोकसभा अध्यक्षों ने सांसदों से राय मशविरा कर सुरक्षा खामियों की समीक्षा की है और जरूरी कदम उठाए हैं। इस बार भी लोकसभा अध्यक्ष के निर्देश के अनुसार, पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच शुरू हो चुकी है और साथ ही सुरक्षा उपायों को मजबूत करने के लिए कदम भी उठाये गए हैं।

प्रह्लाद जोशी ने पुराने मामलों को किया जिक्र

प्रह्लाद जोशी ने लोकसभा की सुरक्षा में चूक के कुछ पुराने मामले भी गिनाए, लेकिन साथ ही यह भी साफ कर दिया कि उनका उद्देश्य किसी पर ऊंगली उठाना नहीं है, बल्कि सिर्फ जानकारी दे रहे हैं। इस सिलसिले में उन्होंने 11 अप्रैल, 1974 को संसद के बजट सत्र के दौरान रतनचंद्र गुप्ता द्वारा दो पिस्तौल और एक बम जैसी चीज लेकर दर्शक दीर्घा तक पहुंचने और पर्चे फेंकने के बारे बताया। इस घटनाक्रम के तीन महीने बाद मानसून सत्र के दौरान विप्लव बसु नाम के व्यक्ति ने खंजर लेकर दर्शक दीर्घा में घुसने की कोशिश की थी। उसके बाद अगले शीतकालीन सत्र के दौरान 26 नवंबर को सत्यजीत सिंह विस्फोटक और खंजर लेकर दर्शक दीर्घा में पहुंच गया। 1999 में 10 और 11 जनवरी को बद्री प्रसाद और पुष्पेंद्र चौहान नाम के दो व्यक्ति ने दो दिन लगातार दर्शक दीर्घा से सदन के भीतर छलांग दी थी। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं की जांच और सुरक्षा की कमियों को दूर करने के साथ ही संसदीय कार्य में बाधा नहीं आयी।

मणिपुर हिंसा के दौरान मारे गए 64 लोगों के शव परिजनों को सौंपे गए, 6 की अब तक पहचान नहीं

नई दिल्ली: मणिपुर में जातीय हिंसा के दौरान मारे गए 64 लोगों के शव गुरुवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उनके परिजनों को सौंप दिए गए। हिंसा की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई एक कमेटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, हिंसा में 175 लोगों की मौत हुई है जिनमें से 169 शवों की पहचान कर ली गई, यानी की 6 शवों की पहचान नहीं हो पाई है। अधिकारियों ने बताया कि ये शव अस्पतालों के मुर्दाघर में रखे हुए थे। मई में मणिपुर में शुरू हुई हिंसा के दौरान मारे गए इन लोगों में से 60 लोग कुकी समुदाय से थे। उन्होंने कहा कि 4 अन्य शव मेइती समुदाय के लोगों के थे।

कुकी और मैतेई समुदायों में भड़की थी हिंसा

बता दें कि मणिपुर में इंफाल घाटी में रहने वाले बहुसंख्यक मेइती और पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले कुकी समुदायों के बीच मई में जातीय हिंसा भड़क गई थी। 'कमेटी ऑन ट्राइबल यूनिटी' नामक संगठन ने एक बयान में कहा,'हिंसा में मारे गए कुकी लोगों' का अंतिम संस्कार शुक्रवार को फैजांग के शहीद कब्रिस्तान में किया जाएगा। संगठन ने अंत्येष्टि क्रिया के लिए शुक्रवार को सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक सदर हिल्स कांगपोकपी के भीतर 12 घंटे के पूर्ण बंद का आह्वान किया है और आम जनता से सहयोग करने की अपील की है।

अगस्त में बनाई गई थी 3 पूर्व जजों की कमेटी

सुप्रीम कोर्ट ने हिंसाग्रस्त मणिपुर में राहत उपायों, मुआवजे और पुनर्वास के काम पर गौर करने के लिए अगस्त में हाई कोर्ट के 3 पूर्व जजों - जस्टिस गीता मित्तल, जस्टिस शालिनी जोशी और आशा मेनन की एक कमेटी बनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी की रिपोर्ट पर मणिपुर में मुर्दाघरों में रखे शवों को दफनाने या दाह-संस्कार सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए थे। रिपोर्ट के मुताबिक, जातीय हिंसा के दौरान 175 लोगों की मौत हुई है जिनमें से 169 शवों की पहचान कर ली गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पहचाने गए 169 शवों में से केवल 81 पर परिजनों ने दावा किया था।

नगर पालिका परिषद के अंतर्गत आने वाले अंबेडकर नगर में सार्वजनिक शौचालय का बुरा हाल है

मुंबई : मसोली नगर के पास अंबेडकर नगर, दहानू नगर परिषद में लगभग 1000 से 1200 की आबादी है। इस स्थान पर नागरिक छोटे-छोटे कमरों में रहते हैं, इसलिए लगभग आठ-दस वर्ष पूर्व नगर परिषद द्वारा 24 शौचालयों वाला एक शौचालय बनवाया गया था, लेकिन शौचालय बनने के बाद रख-रखाव के अभाव में शौचालय काफी जर्जर हो गया है। इसलिए इस क्षेत्र के नागरिकों को स्वच्छ एवं अस्वच्छ शौचालयों में जाकर परेशानी उठानी पड़ती है।

दहानू नगर परिषद के अंबेडकर नगर में सार्वजनिक शौचालय की हालत बेहद खस्ता हो गई है. यहां के अधिकांश शौचालयों के दरवाजे टूटे हुए हैं। अगर आप इस जगह पर रात के समय जाएं तो बिजली की सुविधा नहीं है, छत की सफाई करने वाला कर्मचारी हर हफ्ते छत की सफाई नहीं करता है। तो बदबू दूर हो गई. लेकिन नागरिक नाक दबाकर इन शौचालयों का उपयोग कर रहे हैं क्योंकि इन शौचालयों का उपयोग करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। एक ओर जहां दहानू नगर परिषद दर्शनीय क्षेत्र के सौंदर्यीकरण पर लाखों रुपये खर्च कर रही है. लेकिन नागरिकों का आरोप है कि वे बस्ती में आश्रय स्थलों और कूड़ादानों की उपेक्षा कर रहे हैं. जब चुनाव आता है तो इस क्षेत्र के पार्षद

बड़ी-बड़ी घोषणाएं करते हैं. लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद यहां के नागरिकों की मांग है कि जल्द से जल्द इन शौचालयों की मरम्मत कराई जाए, भले ही वे दोबारा इस इलाके में न घूमें.

हमारे इलाके में सार्वजनिक शौचालयों की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। दरवाजे टूटे हुए हैं. रात को बिजली नहीं. चूंकि दरवाजे टूटे हुए हैं, चयनकर्ता बेहतर शौचालय का उपयोग करते हैं। इससे नागरिकों को असुविधा होती है। -विनोद मायावंशी, आदिवासी अंबेडकरनगर

सरकार की घर-घर शौचालय योजना भी इस क्षेत्र में क्रियान्वित की जा रही है. इसलिए, सार्वजनिक शौचालयों का उपयोग करने वाले अंबेडकर नगर के निवासियों को व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण के लिए 17,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। जिसमें से पहली किस्त जमा हो चुकी है.

डेढ़ साल से प्रमोशन का इंतजार कर रहे 788 सहायक पुलिस निरीक्षक,

सेवानिवृत्ति नजदीक आते ही सपना टूटने के संकेत

ठाणे : आगामी लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय स्वशासन चुनावों के कारण कानून व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से आने वाले वर्ष महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं. लेकिन कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी संभालने वाले पुलिस निरीक्षकों के जहां 540 पद खाली हैं, वहीं पिछले डेढ़ साल से प्रोन्नति का इंतजार कर रहे 788 सहायक पुलिस

निरीक्षकों को प्रोन्नति नहीं मिली है. ऐसे संकेत मिल रहे हैं. पुलिस इंस्पेक्टर बनने का सपना टूट जायेगा.

2010 में राज्य पुलिस बल के बैच संख्या 102 और बैच संख्या 103 में 533 अधिकारी और 530 अधिकारी हैं। इन अधिकारियों को वर्ष 2014 में पुलिस उप-निरीक्षक के पद से सहायक पुलिस कांस्टेबल के पद पर पदोन्नत किया गया था। ये सभी पिछले दस वर्षों से सहायक पुलिस निरीक्षक के पद पर कार्यरत हैं। पुलिस कांस्टेबलों की सेवानिवृत्ति के बाद जैसे ही वे पद रिक्त होते हैं, सहायक पुलिस निरीक्षकों को पदोन्नत किया जाता है। लेकिन पुलिस कांस्टेबल के पद खाली होने के बाद भी उन्हें प्रमोशन नहीं मिलने से अधिकारियों में नाराजगी सामने आने लगी. पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक 2 फरवरी 2022 को हुई। 102 नंबर दस्ते के 533 अधिकारियों में से 275 अधिकारियों को पुलिस निरीक्षक के पद पर प्रोन्नति दी गयी है, जबकि शेष 275 अधिकारियों को प्रोन्नति नहीं दी गयी है. ऐसी उम्मीद थी, लेकिन उनके रैंकों को निराशा हुई है और वे अब भी इंतजार कर रहे हैं. प्रमोशन के लिए. इनमें विभाग के तहत सजायाफ्ता कई लोगों की सेवानिवृत्ति नजदीक आ गयी है और उनकी चिंता बढ़ गयी है कि सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें प्रोन्नति का लाभ नहीं मिलेगा.

विभाग के अंतर्गत जिन पुलिस अधिकारियों को अपराधी घोषित किया गया था, वे वरिष्ठता प्राप्त करने के लिए 'एमएटी' में गए थे। मैट ने उन्हें वरिष्ठता लागू करने का आदेश देकर कार्यमुक्त कर दिया था। राज्य सरकार ने मैट के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है और मामला अदालत में विचाराधीन है। वरिष्ठता का मामला 'मैट' में था, उसी समय 102 नंबर दस्ते के दो सौ अधिकारियों ने पुलिस निरीक्षकों की प्रोन्नति नहीं होने पर 'मैट' में अपील की थी, पुलिस सूत्रों ने बताया कि 'मैट' ने उन्हें राहत तो दी, लेकिन अधिकारी प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं.

गढ़चिरौली में नक्सलियों के साथ पुलिस की मुठभेड़, दो को किया ढेर... भारी मात्रा में हथियार बरामद

महाराष्ट्र : पूर्वी महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में गुरुवार को पुलिस के साथ मुठभेड़ में दो नक्सली मारे गए। इनमें से एक 2019 जंबुलखेड़ा विस्फोट में शामिल था। एक अधिकारी ने बताया कि मारा गया कसानसुर दलम (दस्ते) का डिप्टी कमांडर दुर्गेश वट्टी जंबुलखेड़ा विस्फोट के मुख्य साजिशकताओं में से एक था। 2019 में हुए इस विस्फोट में गढ़चिरौली पुलिस के 15 पुलिसकर्मी मारे गए थे।

जिला पुलिस अधीक्षक नीलोत्पल

ने बताया कि पुलिस को खुफिया जानकारी मिली थी कि नक्सलियों की एक बड़ी टुकड़ी छत्तीसगढ़ सीमा पर गोदलवाही चौकी के पास बोधिनटोला के पास डेरा डाले हुए है। उनका इरादा घुसपैठ करने और पुलिस बलों पर घात लगाकर हमला करने का है।

एके-47 राइफल भी बरामद

उन्होंने बताया कि हमने तत्काल तलाशी अभियान चलाया और इस दौरान नक्सलियों ने पुलिस दल पर गोलीबारी कर दी। करीब एक घंटे तक चली गोलीबारी खत्म होने के बाद वत्ती और एक अन्य पुरुष नक्सली के शव मौके से मिला। मौके से एक एके-47 राइफल और एक सेल्फ-लोडिंग राइफल (एसएलआर) भी बरामद की गई है। इलाके में तलाशी जारी है।

डोंबिवली एमआईडीसी में सीवरों की मिट्टी भरना

डोंबिवली : डोंबिवली एमआईडीसी में कंक्रीट सड़क कार्य के कारण महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम के सबवे सीवर, सड़क से सटे सीवर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। नालों में पांच से सात फीट तक गहरी मिट्टी का भराव हो गया है। डोंबिवली एमआईडीसी के कार्यकारी अभियंता शंकर अवध ने मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन अथॉरिटी के कार्यकारी अभियंता अर्जुन कोरगांवकर को पत्र भेजकर कहा है कि कई जगहों पर सीवर ध्वस्त हो गए हैं और कुछ

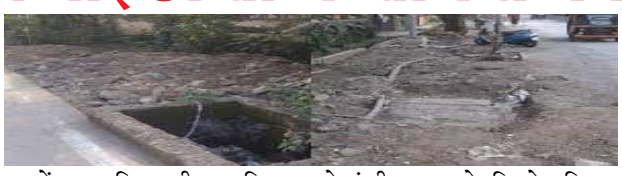

स्थानों पर भूमिगत सीवर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। एमआईडीसी आवासीय औद्योगिक प्रभाग में मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) के माध्यम से 110 करोड़ रुपये का कंक्रीट सड़क कार्य किया गया है। कुछ कार्य प्रगति पर हैं. एमआईडीसी ने कंक्रीट सड़क के किनारे क्षतिग्रस्त भूमिगत नलिकाओं को बदलने, सीवरों में मिट्टी की खुदाई के लिए एक ठेकेदार नियुक्त किया है। एमआईडीसी का काम शुरू होने से पहले ही एमएमआरडीए ने सड़क सीमा से सटे सीवर और नालियों वाले खुले स्थानों को पेवर ब्लॉक लगाकर बंद करने का अभियान शुरू कर दिया है। अगर सब-वे के नीचे काम से पहले पेवर ब्लॉक लगाया गया तो बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। एमआईडीसी प्रशासन ने एमएमआरडीए को सूचित किया है कि किया गया कार्य निःशुल्क होगा। एमआईडीसी ने एमएमआरडीए प्रशासन को सलाह दी है कि यदि पेवर ब्लॉक लगाने का निर्णय बरकरार रखा जाता है, तो नटार, सबवे सीवर के क्षेत्रों में कंक्रीट सड़क की सीमा से कुछ दूरी पर पेवर ब्लॉक नहीं लगाए जाने चाहिए।

मीरा-भाईदर ट्रांसपोर्ट बस टिकट पेटीएम पर...

भाईदरः बस से यात्रा करते समय हमेशा खुले पैसों का लेन-देन होता रहता है। इसके चलते बस कंडक्टरों और यात्रियों के बीच हमेशा विवाद होता रहता है। हालांकि, मीरा-भाईदर नगर निगम की बसों में मुफ्त पैसे की कोई कमी नहीं होगी क्योंकि जल्द ही यात्री मोबाइल फोन में क्यूआर कोड के जरिए बस टिकट प्राप्त कर सकेंगे। नगर निगम सेवाएं

यथासंभव हाईटेक बनने का प्रयास कर रही हैं। इसके तहत यात्रियों को क्यूआर कोड के जरिए बस टिकट लेने की सुविधा दी जाएगी। इस संबंध में पेटीएम कंपनी को स्वीकृति पत्र दिया गया। यह सुविधा अगले माह यात्रियों को मिलने लगेगी। यात्री जिस तरह क्यूआर कोड के जरिए अन्य ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, उसी तरह बस टिकट भी खरीद सकेंगे। ढ८३ ऐप से बस टिकट खरीदने पर उसका दफ कोड जनरेट हो जाएगा. इस क्यूआर कोड को बस में कंडक्टर के पास मौजूद मशीन में स्कैन करना होता है। पेटीएम से जमा टिकट का पैसा अगले दिन नगर निगम के खाते में जमा कर दिया जाएगा। इसके लिए नगर निगम को कोई अतिरिक्त खर्च नहीं आएगा। पेटीएम को स्वीकृति पत्र देने के बाद कंपनी को ट्रांसपोर्ट सर्विस के इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम के साथ एकीकृत कर दिया जाएगा.

शादी समारोह में फूड पॉइजनिंग के कारण 80 लोगों की तबीयत बिगड़ी... रिसॉर्ट प्रबंधन के खिलाफ केस दर्ज

महाराष्ट्र : महाराष्ट्र के नागपुर में फूड पॉइजनिंग के एक संदिग्ध मामले में 80 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के अनुसार ये सभी व्यक्ति नागपुर सिटी के बाहरी क्षेत्र में एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे। यह घटना 10 दिसंबर की है। दुल्हे के पिता ने रिसॉर्ट प्रबंधन के खिलाफ समारोह के दौरान बासी खाना पड़ोसने का आरोप लगाया। शिकायतकर्ता कैलाश बत्रा ने नागपुर के अमरावती रोड के पास राजस्थानी

थीम पर बने रिसॉर्ट के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। दुल्हे के पिता ने बताया कि उन्होंने नौ और दस दिसंबर के लिए रिसॉर्ट बुक किया था। अधिकारी ने बताया कि परेशानी 10 दिसंबर की दोपहर से शुरू हुई, जब दुल्हा समेत अन्य मेहमानों ने खाना खाने के बाद पेट दर्द की शिकायत की। रिसेप्शन सेरेमनी के दौरान हालत और भी ज्यादा खराब हो गई थी। दरअसल, रात में परोसे गए खाने से दुर्गंध आने के बाद शिकायतकर्ता ने रिसॉर्ट के मैनेजर से इसकी शिकायत की, लेकिन इसके बावजूद कोई कदम नहीं उठाया गया। आधी रात में 80 लोगों को उल्टी शुरू हो गई। उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया।

दादाजी घर से बाहर टहलने गए थे तभी दो चोरों ने एक योजना बनाई...

वाशी : वाशी सेक्टर-28 में हुई, जब तेज रफ्तार बाइक पर आए दो लोगों ने उनसे 50 हजार रुपये की सोने की चेन खींच ली। वाशी पुलिस ने इस घटना में दोनों लुटेरों के खिलाफ जबरन चोरी का मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है. इस घटना के शिकायतकर्ता वल्लभदास शाह (81) कोपरखैरणे सेक्टर-11 इलाके में रहते हैं। वह मंगलवार सुबह करीब 9 बजे घर से टहलने के लिए निकले थे।

इसी दौरान जब वे पैदल वाशी सेक्टर-28 पहुंचे तो विजय डेयरी के सामने सड़क पार कर रहे थे तभी तेज रफ्तार बाइक पर आए दो लुटेरों ने वल्लभदास के गले से 60 हजार रुपये कीमत की सोने की चेन खींच ली और भाग गए। इस घटना के बाद वल्लभदास ने अपने रिश्तेदारों के साथ वाशी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई।

दैनिक रोकठोक लेखनी
खबरें बे-रोकटोक
मुंबई : शुक्रवार 15 दिसंबर 2023

अंधेरी में वाटर चैनल मामला: नोटिस देने के बाद भी ठेकेदार की ओर से कोई जवाब नहीं...

मुंबई: पिछले हफ्ते, जब अंधेरी में मेट्रो परियोजना चल रही थी, वेरावली सेवा जलाशय का मुख्य जल चैनल प्रभावित हुआ और भारी पानी का रिसाव हुआ। इसलिए संबंधित क्षेत्र के नागरिकों को चार से पांच दिनों तक बिना पानी के रहना पड़ा। इस घटना से नगर निगम प्रशासन को भी भारी आर्थिक बोझ उठाना पड़ा. जिसके चलते मुंबई नगर निगम ने मेट्रो अथॉरिटी को नोटिस भी जारी किया था कि ठेकेदार पर 1 करोड़ रुपये से ज्यादा का जुमार्ना लगाया गया है. हालांकि, एक सप्ताह बाद भी ठेकेदार ने अभी तक जुमार्ना नहीं भरा है और नगर निगम को ठेकेदार की ओर से कोई जवाब भी नहीं मिला है. 30 नवंबर को जब मेट्रो परियोजना का काम चल रहा था, तब नगर निगम के वेरावली जलाशय के 1800 मिमी व्यास वाले जल चैनल पर असर पड़ा. इससे बड़ी मात्रा में पानी का रिसाव हो गया. मुंबई नगर निगम ने जल चैनल की मरम्मत का काम किया। हालाँकि, साइट पर तकनीकी और भौगोलिक चुनौतियों के कारण, मरम्मत कार्य की अवधि बढ़ गई। जमीन के अंदर गहराई में स्थित यह जलमार्ग एक से अधिक

स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो गया था। साथ ही पानी के भारी दबाव के कारण पानी पंप कर जलमार्ग को पूरी तरह खाली कर दिया गया. परिणामस्वरूप अंधेरी, जोगेश्वरी, विलेपार्ले, घाटकोपर, विद्याविहार आदि इलाकों के नागरिकों को पानी की कमी का सामना करना पड़ा। नागरिकों को असुविधा न हो इसके लिए मुंबई नगर निगम ने टैंकरों के जरिए पानी की आपूर्ति की. हालाँकि, वह असफल रहा। कई नागरिकों को पानी खरीदना पड़ा. इस रिसाव के कारण लाखों लीटर पानी बर्बाद हो गया। नगर पालिका को आर्थिक बोझ भी उठाना पड़ा। इसके अलावा नगर पालिका ने संबंधित अधिकारियों को वाटर चैनल की जानकारी देकर सावधानी बरतने की सलाह दी थी। लेकिन काम में ढिलाई के कारण यह घटना घटी. इसलिए नगर निगम प्रशासन ने ईगल इंफ्रा इंडिया लिमिटेड, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, मुंबई मेट्रो अथॉरिटी आदि को कुल मिलाकर 10 लाख रुपये का भुगतान करने का नोटिस भेजा था। हालांकि एक सप्ताह बाद भी नगर पालिका को उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला है।

एमबीबीएस प्रथम वर्ष के फेल छात्रों को परीक्षा देने का एक और मौका

मुंबई: शैक्षणिक वर्ष 2020-2021 में प्रवेश लेने वाले छात्रों को कोरोना के कारण कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसका असर छात्रों की पढ़ाई पर पड़ा है. परिणामस्वरूप कुछ विद्यार्थियों को परीक्षा में असफलता का सामना करना पड़ रहा था। इसे ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने उन एमबीबीएस छात्रों को एक और मौका देने का फैसला

किया है, जो शैक्षणिक वर्ष 2020-2021 में प्रवेश ले चुके हैं और पहली परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाए हैं। कोरोना में मेडिकल छात्रों को मरीजों की देखभाल के साथ-साथ महामारी का भी सामना करना पड़ा। इस वजह से कई लोग मानसिक रूप से परेशान थे. इससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हुई. इसके चलते कई छात्र एमबीबीएस परीक्षा में फेल हो गए। इसे ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने उन छात्रों को एक अतिरिक्त अवसर देने का निर्णय लिया है, जिन्होंने मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश लिया है और शैक्षणिक वर्ष 2020-21 में एमबीबीएस प्रथम वर्ष की परीक्षा में असफल हो गए हैं।

यूपी के बाद महाराष्ट्र में हलाल प्रोडक्ट्स पर बैन की मांग

मुस्लिम नेताओं और मौलानाओं ने जताया विरोध

उत्तर प्रदेश : उत्तर प्रदेश की तर्ज पर महाराष्ट्र में भी हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स पर पाबंदी लगाने की मांग की जाने लगी है। सत्तापक्ष एकनाथ शिंदे की शिवसेना गुट के विधायक और हिंदूवादी संगठनों ने ये मांग की है। इस मांग को लेकर एक पत्र महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लिखा गया है। महाराष्ट्र विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान शिवसेना शिंदे गुट के विधायक प्रताप सरनाईक, मनीष कायदे साथ ही हिंदू जनजागृति समिति ने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने लिखा कि महाराष्ट्र में हलाल सर्टिफिकेट पर पाबंदी लगाई जाए।

महाराष्ट्र में हलाल सर्टिफिकेट पर बैन की मांग

शिवसेना नेता और हिंदूवादी संगठनों के इस मांग पर मुस्लिम नेताओं और मौलानाओं ने विरोध जताया है। इस बाबत वारिस पठान ने कहा कि सरकार बेवजह ही किसी मुद्दे को तूल दे रही है। उनका कहना है कि सरकार हिंदू-मुस्लिम में झगड़ा लगाने का काम कर रही है। हलाल सर्टिफिकेट पहले से दिया जाता है। सरकार हिंदू तुष्टिकर और वोटबैंक की राजनीति कर रही है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने इस बाबत कहा कि सत्ता पक्ष के विधायकों की मांग और हिंदूवादी संगठनों की मांग के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अभी तक कोई ठोस फैसला नहीं लिया है।

अबू आजमी ने सरकार को कहा नफरत के पुजारी

अबू आजमी ने कहा कि मुसलमानों को हलाल खाना चाहिए, हराम खाने की हमें मनाही है। मुसलमान हलाल खाता है इसलिए सरकार मुसलमानों के खिलाफ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि नफरत के पुजारियों के इस तरह का काम बंद कर देना चाहिए।

वसई में नयना महंत हत्याकांड में 622 पेज की चार्जशीट

सरसों के पौधे और नल का पानी अहम सबूत

वसई: नयना महंत की हत्या मामले में नायगांव पुलिस ने वसई सेशन कोर्ट में 622 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है. इस मामले में उसका प्रेमी मनोहर शुक्ला और उसकी पत्नी पूर्णिमा आरोपी हैं। इस चार्जशीट में 27 लोगों ने अपने बयान दिए हैं और शव के पास मौजूद सरसों का पौधा और जिस बाल्टी में उसे डुबाया गया था उसका पानी अहम सबूत हैं. 9 फिल्मों में हेयरड्रेसर का काम कर चुकीं नैना महंत (28) की 1 सितंबर को उनके बॉयफ्रेंड मनोहर शुक्ला ने हत्या कर दी थी। इसके बाद पत्नी पूर्णिमा शुक्ला की मदद से नयना का शव गुजरात के वलसाड ले जाया गया. इस मामले में नायगांव पुलिस ने शुक्ला दंपत्ति को गिरफ्तार कर लिया है. नायगांव पुलिस ने मामले की जांच पूरी कर ली है और वसई की सेशन कोर्ट में 622 पेज की चार्जशीट दाखिल कर दी है. कुल 27 लोगों ने प्रतिक्रिया दी है. नयना के शव

को एक बैग में पैक किया गया और स्कूटर पर शुक्ला दंपति क्लासांग ले गए। बैग को लिफ्ट से नीचे लाया गया. इसमें उस पर नजर रखने वाले सुरक्षा गार्ड की जिम्मेदारी भी शामिल है.

सरसों एवं पानी की बाल्टी महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं

9 सितंबर को मनोहर शुक्ला ने विवाद के बाद नैना महंत का मुंह पानी की बाल्टी में डुबाकर मार डाला। मेडिकल जांच में उसके फेफड़ों में पानी होने की बात सामने आई। उसने उस बाल्टी से पानी निकाल लिया है जिसमें उसने नयना का चेहरा डुबोया था। रासायनिक परीक्षण से सिद्ध हो गया है कि जल वही है। इस के अलावा नयना की लाश की दुर्गंध से बचने के लिए सूटकेस में आधा किलो सरसों के बीज डाल दिए. उन्होंने शव को गुजरात राज्य के वलसाड के पास पारदी में पार नदी के किनारे फेंक दिया और सूटकेस को दूर फेंक दिया क्योंकि उन्हें लगा कि सरसों के बीज के कारण सड़ने के कारण शव से दुर्गंध नहीं आएगी। आरोप पत्र में कहा गया है कि घटनास्थल पर सरसों के बीज की जड़ें और उनके अंकुर फूटना भी सबूत हैं। कुछ बच्चों को आरोपी द्वारा गिराए गए सूटकेस मिल गए। उसमें सरसों के बीज थे. उन्होंने पुलिस को बताया कि हालांकि पुलिस को सूटकेस नहीं मिला, लेकिन उसमें सरसों के बीज थे. उनका जवाब भी आरोपपत्र में संलग्न किया गया है. इसे उस दुकानदार के बयान के साथ संलग्न किया गया है जहां से आरोपी ने 1.5 किलोग्राम सरसों के बीज खरीदे थे।

एक्ट्रेस का न्यूड वीडियो हुआ वायरल, इस तरह कई युवतियों के फंसने की आशंका है

वसई: एक अभिनेत्री को फिल्म में काम दिलाने की बात कहकर ऑडिशन के नाम पर अश्लील फिल्म बनाई गई। लेकिन उसे गुमराह कर इसे अश्लील वेब सीरीज में प्रसारित किया गया है. अनार्ला सागरी पुलिस स्टेशन में 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. इस मामले की जांच अब क्राइम ब्रांच 3 को सौंप दी गई है... पीड़िता 18 साल की है और एक्ट्रेस बनने के लिए मुंबई आई है. फिलहाल वह वसई में किराए के मकान में रहती हैं। वह हिंदी सिनेमा और वेव सीरीज में काम पाने के लिए कई प्रोडक्शन हाउस (प्रोडक्शन हाउस) के चक्कर लगा रही थीं। इसी बीच एक नवंबर को उसके पास एक कंपनी से फोन आया। एक्ट्रेस को बताया गया कि हम एक नई बेव सीरीज बना रहे हैं और ऑडिशन के लिए आना होगा। युवती 2 नवंबर को काम की तलाश में विरार के अनार्ला बीच पर गई थी. वहां उनकी मुलाकात

इस प्रोडक्शन कंपनी के 4 लोगों से हुई, जिनमें एक डायरेक्टर, एक कैमरामैन, एक एक्टर और एक महिला मेकअप आर्टिस्ट शामिल थे।

चारों उसे ऑडिशन के लिए एक लॉज में ले गए। वहां उसे यह कहकर धोखे में रखा गया कि वह कुछ सीन फिल्माना चाहती है और एक अश्लील सीन देना चाहती है। उन्हें बताया गया कि ये दृश्य केवल ऑडिशन का एक हिस्सा हैं और इनका कहीं भी उपयोग नहीं किया जाता है, जैसा कि फिल्म उद्योग में किया जाना चाहिए। इस वजह से यह युवती बेबस थी. लेकिन उसके बाद उन्हें इस कंपनी में किसी का फोन नहीं आया. इस बीच, उसने संबंधित लोगों को फोन किया क्योंकि उसे अपने परिचितों से जानकारी मिली कि उसके दृश्य अश्लील वेब श्रृंखलाओं में अपलोड किए गए थे, जो विभिन्न अश्लील वेबसाइटों पर प्रसारित किए गए थे, लेकिन उनके नंबर बंद थे। जब उसे एहसास हुआ कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है, तो उसने अनार्ला सागरी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और धोखाधड़ी की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। मामले को आगे की जांच के लिए अपराध शाखा 3 को स्थानांतरित कर दिया गया है। कुछ साल पहले एक बड़ी हस्ती नवोदित अभिनेत्रियों को धोखा देकर उनके अश्लील टेप बनाने के ऐसे ही मामले में शामिल थी। पुलिस ने बताया कि यह उसी प्रकार का मामला है. इस मामले में नवोदित युवतियों को ठगने के लिए एक गिरोह काम कर रहा है।

मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक फैसल शेख ने सोमानी प्रिन्टिंग प्रेस, गाला नं.4, एन. के. इंडस्ट्रीयल इस्टेट, प्रवासी इंडस्ट्रीयल इस्टेट के अंदर, गेट नं. 2, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई- 400063 से छपवाकर रूम नं 15 रमजान बिन 17 सी वंजावडी, माहिम वेस्ट मुंबई :4000 16 से प्रकाशित किया। संपर्क कार्यालय : शॉप नंबर ४ , मदीना मेंशन, ८१ ए, कैडल रोड, अपोजिट बिल्लाबोंग स्कूल, माहिम पश्चिम, मुंबई ४०००१६ , महाराष्ट्र मोबाइल नं 998777 5650 व्हाट्सप्प नं 7977408589: Email-editor@rokthoklekhaninews.com